

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 जनवरी 2022 — माघ 11, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 29 जनवरी 2022

क्र. 912/डी. 03/21-अ/प्रारू./छ.ग./22. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 06-01-2022 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 2 सन् 2022)

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) को और संशोधन करने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | | |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. | 1. | (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलायेगा ।
(2) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करें: |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

- | | | |
|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| धारा 7 का संशोधन. | 2. | छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र. 7 सन् 2017) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये और 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात् :- |
|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

“(कक) किसी व्यक्ति, जो किसी व्यक्ति से भिन्न है, के द्वारा उसके सदस्यों या घटकों या विपर्येन से नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रियाकलाप या संव्यवहार ;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी न्यायालय, अभिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति और उसके सदस्यों या घटकों को दो पृथक् व्यक्ति समझा जाएगा और क्रियाकलापों का प्रदाय या संव्यवहार, परस्पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया समझा जायेगा ।”

3. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

धारा 16 का
संशोधन.

“(कक) खंड (क) में निर्दिष्ट बीजक या नामे नोट के ब्यौरे पूर्तिकार द्वारा बहिगामी पूर्ति के विवरण में प्रस्तुत किए गए हैं और ऐसे ब्यौरे, धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में ऐसे बीजक या नामे नोट के प्राप्तिकर्ता को संसूचित किए गए हैं।”

4. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (5) का लोप किया जाए ।
5. मूल अधिनियम की धारा 44 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

धारा 35 का
संशोधन.

धारा 44 का
संशोधन.

“(44) वार्षिक विवरणी.— किसी इनपुट सेवा वितरक से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति, इलेक्ट्रानिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति, जैसा कि विहित किया जाए, में संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ एक

वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित पूर्तियों के मूल्य के साथ सुमेलित करते हुए, एक स्वप्रमाणित सुमेलन विवरण सम्मिलित किया जा सकेगा :

परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस धारा के अधीन वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने से छूट प्रदान कर सकेगा :

परंतु यह और कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी को, जिनकी लेखाबहियां, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा, या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा, संपरीक्षा के अध्वधीन हैं, लागू नहीं होगी।”

धारा 50 का
संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए और 1 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु धारा 39 के उपबंधों के अनुसार, किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में और शोध्य तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत विवरणी में घोषित संदेय कर पर ब्याज, सिवाय वहां के जहां ऐसी विवरणी उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ होने के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, कर के उस भाग के लिए

संदेय होगा, जिसे इलेक्ट्रानिक नकद लेजर से विकलन करके संदत्त किया जाता है।”

7. मूल अधिनियम की धारा 74 के स्पष्टीकरण (1) के खंड (ii) में, शब्द एवं अंक “तो धारा 122, धारा 125, धारा 129 और धारा 130 के” के स्थान पर, शब्द एवं अंक “तो धारा 122 और धारा 125 के” प्रतिस्थापित किया जाये। धारा 74 का संशोधन.

8. मूल अधिनियम की धारा 75 की उपधारा (12) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :- धारा 75 का संशोधन.

“स्पष्टीकरण :- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, शब्द “स्वनिर्धारित कर” में धारा 37 के अधीन प्रस्तुत किए गए ऐसी बहिर्गामी पूर्तियों के व्यौरों के संबंध में संदेय कर, शामिल होगा, किन्तु धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में शामिल नहीं किया जायेगा।”

9. मूल अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :- धारा 83 का संशोधन.

“(1) जहां अध्याय 12, अध्याय 14 या अध्याय 15 के अधीन किसी कार्यवाही के आरंभ होने के पश्चात्, आयुक्त की यह राय है कि सरकारी राजस्व के हित की संरक्षा करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह लिखित में, आदेश द्वारा, ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाए, धारा 122 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कराधेय व्यक्ति या किसी व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता भी है, को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा।”

धारा 107 का
संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) के खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“परंतु धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन, किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक प्रस्तुत नहीं की जाएगी, जब तक कि शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का, अपीलार्थी द्वारा संदाय न कर दिया गया हो।”

धारा 129 का
संशोधन.

11. मूल अधिनियम की धारा 129 में,—

(एक) उपधारा (1) के खंड (क) और (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(क) ऐसे माल पर संदेय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर की कोई रकम या पच्चीस हजार रुपए, जो भी कम हो, के संदाय पर, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है ;

(ख) माल के मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति या ऐसे माल पर संदेय कर का दो सौ प्रतिशत के संदाय पर, जो भी अधिक हो और छूट प्राप्त माल की दशा में, ऐसे माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर की कोई रकम या पच्चीस हजार रुपए, जो भी कम हो, के संदाय पर, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है ;”

(दो) उपधारा (2) का लोप किया जाये;

(तीन) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(3) माल या वाहनों को निरुद्ध या उनका अभिग्रहण करने वाला समुचित अधिकारी, यथास्थिति, निरोध या अभिग्रहण किए जाने के सात दिन के भीतर संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और तत्पश्चात्, उपधारा (1) के खंड (क) या (ख) के अधीन शास्ति के संदाय के लिए ऐसी नोटिस की तामील की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा।”

(चार) उपधारा (4) में, शब्द “ब्याज या शास्ति” के स्थान पर, शब्द “शास्ति” प्रतिस्थापित किया जाये ;

(पांच) उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी, उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उपधारा (1) में यथा उपबंधित शास्ति की रकम का संदाय करने में असफल रहता है, तो इस प्रकार निरुद्ध या अभिगृहीत माल या वाहन, उपधारा (3) के अधीन शास्ति की वसूली के लिए ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए, विक्रय किए जाने या अन्यथा निपटाए जाने का दायी होगा :

परंतु परिवहनकर्ता द्वारा उपधारा (3) के अधीन शास्ति के संदाय पर या एक लाख रुपये, इनमें से जो भी

कम हो, का संदाय किए जाने पर वाहन को निर्मुक्त किया जाएगा :

परंतु यह और कि जहां निरुद्ध या अभिगृहीत किया गया माल, नष्ट होने वाला या परिसंकटमय प्रकृति का है या समय के साथ उसके मूल्य में हास होने की संभावना है, वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि, समुचित अधिकारी द्वारा, ऐसे समय के लिए, जो वह ठीक समझे, कम की जा सकेगी।”

धारा 130 का
संशोधन.

12. मूल अधिनियम की धारा 130 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द “इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई” के पूर्व, शब्द “जहां” अंतस्थापित किया जाये ;

(ख) उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में, शब्द, कोष्टक और अंक “धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति की रकम” के स्थान पर, शब्द “ऐसे माल पर संदेय कर के एक सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति” प्रतिस्थापित किया जाये ;

(ग) उपधारा (3) का लोप किया जाये।

धारा 151 का
संशोधन.

13. मूल अधिनियम की धारा 151 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“151. सूचना मांगने की शक्ति.— आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के

संबंध में व्यवहृत किसी मामले के संबंध में, कोई सूचना प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगा।”

14. मूल अधिनियम की धारा 152 में,—

धारा 152 का संशोधन.

(क) उपधारा (1) में,—

(एक) शब्द “किसी व्यक्ति विवरणी या उसके भाग की” का लोप किया जाये ;

(दो) शब्द “ऐसी सूचना” के पश्चात्, शब्द “संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना” अंतःस्थापित किया जाये ;

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाये।

15. मूल अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 7 का लोप किया जाये और 1 जुलाई, 2017 से लोप किया गया समझा जाएगा।

अनुसूची 2 का संशोधन.

अटल नगर, दिनांक 29 जनवरी 2022

क्र. 912/डी. 03/21-अ/प्रारू./छ.ग./22. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (क्रमांक 2 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 2 of 2022)

THE CHHATTISGARH GOODS AND SERVICES TAX
(AMENDMENT) ACT, 2021.

An Act further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Second Year of the Republic of India, as follows:-

Short title and commencement. 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021.

(2) It Shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

Amendment of Section 7. 2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017), (hereinafter referred to as the Principal Act), after clause (a) of sub-section (1) of Section 7,

the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:-

“(aa) the activities or transactions, by a person, other than an individual, to its members or constituents or vice-versa, for cash, deferred payment or other valuable consideration;

Explanation:- For the purposes of this clause, it is hereby clarified that, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any judgment, decree or order of any Court, tribunal or authority, the person and its members or constituents shall be deemed to be two separate persons and the supply of activities or transactions inter se shall be deemed to take place from one such person to another.”

**Amendment of
Section 16.**

3. After clause (a) of sub-section (2) of Section 16 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:-

“(aa) the details of the invoice or debit note referred to in clause (a) has been furnished by the supplier in the statement of outward supplies and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under Section 37;”

**Amendment of
Section 35.**

4. Sub-section (5) of Section 35 of the Principal Act shall be omitted.

**Amendment of
Section 44.**

5. For Section 44 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“44. Annual return.- Every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under Section 51 or Section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person shall furnish an annual

return which may include a self-certified reconciliation statement, reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year, with the audited annual financial statement for every financial year electronically, within such time and in such form and in such manner as may be prescribed:

Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt any class of registered persons from filing annual return under this Section:

Provided further that nothing contained in this Section shall apply to any department of the Central Government or a State Government or a Local Authority, whose books of account are subject to audit by the Comptroller and Auditor-

General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force.”

**Amendment of 6.
Section 50.**

For the proviso of sub-section (1) of Section 50 of the Principal Act, the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—

“Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of Section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under Section 73 or Section 74 in respect of the said period, shall be payable on that portion of the tax which is paid by debiting the electronic cash ledger.”

7. In clause (ii) of Explanation 1 of Section 74 of the Principal Act, for the words and figures "Sections 122, 125, 129 and 130", the words and figures "Sections 122 and 125" shall be substituted. **Amendment of Section 74.**
8. After sub-section (12) of Section 75 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:— **Amendment of Section 75.**
- “Explanation:— For the purposes of this sub-section, the expression "self-assessed tax" shall include the tax payable in respect of details of outward supplies furnished under Section 37, shall not included in the return furnished under Section 39.”
9. For sub-section (1) of Section 83 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:— **Amendment of Section 83.**
- “(1) Where, after the initiation of any proceeding under Chapter XII, Chapter XIV or Chapter XV, the Commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting

the interest of the Government revenue it is necessary so to do, he may, by order in writing, attach provisionally, any property, including bank account, belonging to the taxable person or any person specified in sub-section (1A) of Section 122, in such manner as may be prescribed.”

**Amendment of
Section 107.**

10.

After clause (b) of sub-section (6) of Section 107 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:—

“Provided that no appeal shall be filed against an order under sub-section (3) of Section 129, unless a sum equal to twenty-five percent of the penalty has been paid by the appellant.”

**Amendment of
Section 129.**

11.

In Section 129 of the Principal Act,—

- (i) for clause (a) and (b) of sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

“(a) on payment of penalty equal to two hundred percent of the tax payable on such goods and, in case of exempted goods, on payment of an amount equal to two percent of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods comes forward for payment of such penalty;

(b) on payment of penalty equal to fifty percent of the value of the goods or two hundred percent of the tax payable on such goods, whichever is higher, and in case of exempted goods, on payment of an amount equal to five percent of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods does not come forward for payment of such penalty;”

(ii) sub-section (2) shall be omitted;

(iii) for sub-section (3), the following shall be substituted, namely:—

“(3) The proper officer detaining or seizing goods or conveyance shall issue a notice within seven days of such detention or seizure, as the case may be, specifying the penalty payable, and thereafter, pass an order within a period of seven days from the date of service of such notice, for payment of penalty under clause (a) or (b) of sub-section (1).”

(iv) in sub-section (4), for the words “No tax, interest or penalty”, the words “No penalty” shall be substituted;

(v) for sub-section (6), the following shall be substituted, namely:—

“(6) Where the person transporting any goods or the owner of such goods fails to pay the amount of penalty as provided under sub-section (1) within fifteen days from the date of receipt of the copy of the order passed under sub-section (3), the goods or conveyance so detained or seized shall be liable to be sold or disposed of otherwise, in such manner and within such time as may be prescribed, to recover the penalty payable under sub-section (3):

Provided that the conveyance shall be released on payment by the transporter of penalty under sub-section (3) or one lakh rupees, whichever is less:

Provided further that where the detained or seized

goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer, for such period, as he think fit.”

**Amendment of
Section 130.**

12. In Section 130 of the Principal Act,–

- (a) in sub-section (1), before the words “Notwithstanding anything contained in this Act, if”, the word “Where” shall be inserted;
- (b) in sub-section (2), in the second proviso, for the words, brackets and figures “amount of penalty leviable under sub-section (1) of Section 129”, the words “penalty equal to hundred percent of the tax payable on such goods” shall be substituted;

(c) sub-section (3) shall be omitted.

- 13.** For Section 151 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:-

**Amendment of
Section 151.**

“151. Power to call for information.-

The Commissioner or an officer authorised by him may, by an order, direct any person to furnish information relating to any matter dealt with in connection with this Act, within such time, in such form, and in such manner, as may be specified therein.”

- 14.** In Section 152 of the Principal Act,-

**Amendment of
Section 152.**

(a) in sub-section (1),-

(i) the words “of any individual return or part thereof” shall be omitted;

(ii) after the words “any proceedings under this Act”,

the words “without giving an opportunity of being heard to the person concerned” shall be inserted;

(b) sub-section (2) shall be omitted.

**Amendment to 15.
Schedule II.**

Paragraph 7 of Schedule II of the Principal Act shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st day of July, 2017.